केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,
वस्तु एवं सेवा कर भवन,
सातवीं मंजिल पोलिटेकनिक के पास,
आम्बावाडी अहमदाबाद-380015
GST Building, 7th Floor, Near Polytechnic, Ambavadi, Ahmedabad-380015
सत्यमेव जयते
079-26305065 टेलेफेक्स: 079 - 26305136

क फाइल संख्या :File No : **V2/103/GNR/2018-19** 6117-to-6122

ख अपील आदेश संख्या :Order-In-Appeal No.: **AHM-EXCUS-003-APP-73-18-19**

दिनाँक Date :**23.08.2018** जारी करने की तारीख Date of Issue: 6/9/2018

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by **Shri Uma Shanker** Commissioner (Appeals) Ahmedabad

ग अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-III आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश : **AHM-STX-003-JC-AKS-001-18-19** दिनाँक : **04-06-2018** से सृजित

Arising out of Order-in-Original: **AHM-STX-003-JC-AKS-001-18-19,** Date: **04-06-2018**
Issued by: ,CGST, Div:, Gandhinagar Commissionerate, Ahmedabad.

ध **अपीलकर्ता** एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the **Appellant** & Respondent

M/s. NARNARAYAN INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूवोक्त धारा को उप–धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- ण0बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016.

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इ.ए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरूद्व अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any

nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि–1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall beer a court fee stamp of Rs.6.50 paisa as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।
Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिनांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
(ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,
Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Narnarayan Infrastructure Pvt. Ltd., Plot No.522/1, GH-6 Corner, Sector-22, Gandhinagar-382022 (in short 'appellant') against Order-in-Original No. AHM-STX-003-JC-AKS-001-18-19 dtd.04.06.2018 (in short 'impugned order') passed by the Joint Commissioner, Central GST & Excise, Gandhinagar Commissionerate (in short 'adjudicating authority').

2. Briefly stated that an inquiry was conducted against the appellant which revealed that they had failed to pay service tax on transport expenses incurred by them under Reverse Charge Mechanism. Hence, show cause notice dated 23.10.2012 was issued for recovery of service tax of Rs.18,25,358/- for the period 2007-08 to 2011-12. This SCN was adjudicated by the adjudicating authority vide impugned order under which demand of service tax of Rs.18,25,358/- was confirmed along with interest under the provisions of section 73(1) and 75 of the Finance Act, 1994 respectively and penalty under Section 76, 77(1)(a), 77(2) and 78 ibid were imposed.

3. Aggrieved with the impugned order, the appellant has filed present appeal wherein they, *inter alia*, contested that:

- Most of the transporters charged service tax in the invoice itself and collected the same from them hence they were of the view that service tax on transport of goods by road is to be paid by transporters only. Out of total freight of Rs.6.70 crores, service tax liability on Rs.4.03 crores has already been discharged by the transporters. They were under bonafide belief that the liability for payment of service tax is on the transporter in view of union FM speech, inter alia, that there is no intention to levy service tax on truck owners or truck operators.
- They are not liable to pay tax on ourchase of consumable materials accounted under the head 'Transportation Expenses'.
- Entire demand is time barred.
- Penalty cannot be imposed under section 76,77 and 78 in the present case.
- Section 80 will be applicable in the present case.

4. Personal hearing in the matter was held on 26.07.2018. Shri Vipul Khandhar, CA, appeared on behalf of the appellant and reiterated the grounds of appeal memorandum.

5. I have carefully gone through the appeal memorandum and submission made at the time of personal hearing. I find that main issue involved is whether the appellant is liable to pay service tax under RCM under the category of 'Goods Transport Agency service' or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

6. At the out-set, I find that the case was remanded back to the adjudicating authority vide OIA No.129/14-15 dated 23.12.2014 passed by this appellate forum. I also find that the case was remanded for cross verification and ascertaining duty liability of the appellant with clear findings on the subject matter by the then Commissioner(Appeals) vide order supra. However, I find that it has again come up with this authority since the adjudicating authority has passed the impugned order that too after a period of over 3 years in a casual manner without following the direction given in the said OIA, without application of mind, without considering the submissions put-forth by the appellant and without following the judicial discipline on the subject matter. I find that the adjudicating authority is duty bound and should have followed the order passed by this appellate forum scrupulously. Such deliberate dis-obeying of the said order is contemptuous. Once the remand is ordered, lower authorities are deprived of power to reject; otherwise, the appellate hierarchy will serve no purpose. The adjudicating authority can distinguish only where factual matrix alters. Disposing of case in a casual manner where the appellant has to come again after decision by this authority is amounting to washing off hand by the adjudicating authority to decide the case on merits. This act of adjudicating authority has not only led to unwanted and prolonged litigation but also has put needless burden on the appellant. Not following the order of higher appellate forum is gross violation of judicial discipline as held in a catena of judgment of the jurisdictional high courts. I find that the Hon'ble High Court of Gujarat in case of Lubi Industries LLP Vs. UOI reported in 2017(52) STR-95 (Guj.) has held as under:

> ***"Adjudication - Judicial discipline - Identical issue already been decided by CESTAT in favour of petitioner, despite which the adjudicating authority had once again given a decision against the petitioner - HELD : Assistant Commissioner committed a serious error in ignoring the binding judgment of superior Court that too in case of the same assessee - Departmental Authorities would be bound by the judicial pronouncements of the statutory Tribunals - Even if decision of Tribunal was not carried further in appeal on account of low tax effect, it was not open for the adjudicating authority to ignore the ratio of such decision - Only choice open for adjudicating authority was to decide the case in consonance with the judgment of Tribunal and thereafter leave it to Departmental Authorities to decide the question of filing appeal against such an***

order, if otherwise permissible in law - Impugned order set aside - Sections 35 and 35E of Central Excise Act, 1944. [paras 6, 7]"

Accordingly, once again I remand the case back to the adjudicating authority to decide a fresh, within 30 days of receipt of this order, after observing the principle of natural justice. The appellant is also directed to co-operate the adjudicating authority.

7. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है। The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.

(उमा शंकर)
केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Attested:

(B.A. Patel)
Supdt.(Appeals)
Central GST, Ahmedabad.

BY SPEED POST TO:

M/s. Narnarayan Infrastructure Pvt. Ltd.,
Plot No.522/1, GH-6 Corner, Sector-22,
Gandhinagar-382022.

Copy to:-

(1) The Chief Commissioner, CGST, Ahmedabad Zone.
(2) The Commissioner, CGST, Gandhinagar (RRA Section).
(3) The Joint Commissioner, CGST, Gandhinagar.
(4) The Asstt. Commissioner, CGST, Division Gandhinagar.
(5) The Asstt. Commr(System), CGST , Gandhinagar. (for uploading OIA on website)
(6) Guard file
(7) P.A. file.